

institution, it is up to him to supply the information or not. Unfortunately, very few of those who receive training supply information about their subsequent employment or work.

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि जिन लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के पेशों की शिक्षा दी जाती है उन शिक्षित लोगों को सरकार नौकरी में लगा लेती है या उनको बाहरी काम में लगाया जाता है। और क्या ऐसे भी कोई लोग हैं जिनको अभी तक काम नहीं मिला है ?

श्री ए० पी० जैन : सरकार के पास तो आम तौर से कोई काम होता नहीं है, लेकिन जो निजी तौर से उद्योग घंघ करने वाले लोग होते हैं उनके यहां इन लोगों को नौकरी मिल जाती है या वह अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने काम नहीं किया और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको काम नहीं मिल सका।

Shri B. K. Das: With reference to answers to parts (a) and (b) of the question, may I have separate figures with regard to West Bengal?

Shri A. P. Jain: The number of displaced persons trained in West Bengal in vocational trades up to 31st March 1952 was 7,528. The number proposed to be trained in 1952-53 is 11,970.

Sardar Hukam Singh: Have Government considered the question of taking up a survey to find out what number or percentage of trainees have really been employed in any vocation?

Shri A. P. Jain: I cannot promise that. It is a question of money. The trainees are spread all over India and what would be the amount required

for carrying out such a survey has yet to be investigated. Whether it would be worth while carrying out such a survey, I do not know.

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग स्वयं अपना पेशा शुरू करना चाहते हैं उन्हें क्या सरकार कोई धन लोन के रूप में देती है।

श्री ए० पी० जैन : जी हाँ, देती है और अभी जो एक नई विधि निकाली गई थी उसमें कहा गया था कि आइन्दा जो छोटे कर्ज हैं वह उन्हीं लोगों को दिये जायेंगे जो इस प्रकार के कामों की शिक्षा पा कर के निकलेंगे। उस बात पर अमल किया जायेगा ?

नदी घाटी परियोजनाएं

***१७८८. सैठ गोविन्द दास :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा हाथ में ली गई नदी घाटी परियोजनाओं से भारत के किन भागों को लाभ पहुंचने की प्रत्याशा है और किस वर्ष से ये परियोजनायें खाद्यान्न-उत्पादन की वृद्धि में सहायता देने लगेंगी ?

The Minister of Finance (Shri C. D. Deshmukh): The Government of India have not directly undertaken any river valley project in India. However, they are financing the execution of the Hirakud, Bhakara-Nangal and Damodar Valley Projects. A statement is placed on the Table of the House indicating the areas benefited by these schemes and the year in which they will begin to help in further food production.

STATEMENT

| Name of Project | Areas to be benefited | Year from which further food production will result. |
|-------------------------|--|--|
| Bhakra-Nangal | Hissar, Rohtak, Karnal and Ferozpur districts of Punjab (I) ; Bikaner division in Rajasthan and Patiala district in PEPSU. | 1951-52 |
| Hirakund | Sambalpur, Cuttack and Puri districts in Orissa State. | 1955-56 |
| Damodar Valley Schemes. | Burdwan, Howrah, Hooghly and Bankura districts in West Bengal. | 1952-53 |

सेठ गोविन्द दास : जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने रखा है, क्या उसमें से वह यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह तीनों योजनायें कब से काम करना शुरू कर देंगी।

श्री सी० डी० देशमुख : वर्ष तो बताया है।

सेठ गोविन्द दास : वही मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो स्टेटमेंट पढ़ा है।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने तो देखा है बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसलिये मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि कौनसे वर्ष में यह तीनों काम शुरू होंगे।

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट में दिया है।

सेठ गोविन्द दास : मैं केवल उन वर्षों की संख्या जानना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: Let him put any other question.

श्री राधे लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन तीन प्रोजेक्ट्स का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है उसमें नहरें बनाने का खर्चा प्रति मील क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसका अलग विवरण तो मेरे पास नहीं है।

Shri B. R. Bhagat: May I know what steps Government have taken on the recommendations of the Estimates Committee for the efficient and early execution of these three projects?

Shri C. D. Deshmukh: The report is still under consideration.

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा यह सवाल हिन्दी में दिया गया है, और जो सवाल हिन्दी में दिये जाते हैं उनका उत्तर हिन्दी में क्यों नहीं मिलता, उनका उत्तर अंग्रेजी में क्यों मिलता है।

Mr. Speaker: English is permitted; even now I am replying in English.

सेठ गोविन्द दास : मैं यह आशा करता हूँ कि जो मंत्री महोदय हिन्दी जानते हैं वह हिन्दी के प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में दें।

Mr. Speaker: I think I shall not be within constitutional limits to ask them to do it. They may do it of their own accord. I will never object to that; I may encourage that. But, I cannot ask them to reply in Hindi. There are a large number of Members who might feel that they can better understand in English.

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूँ कि चम्बल रिवर वैली योजना के खर्च के लिये, जिसको कि प्रान्तीय सरकार पूरा नहीं कर सकती है, प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खर्च की मांग की है, और यदि की है तो केन्द्रीय सरकार क्या उस प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सम्भव है कि वह अपने बल से इस योजना को पूरा न कर सकती हो। और यह सब प्रश्न नियोजन समिति के सामने हैं।

Mr. Speaker: Next question.

Shri Sarangdhar Das: One question, Sir.

Mr. Speaker: I have called the next question.

निष्क्रमणार्थी संपत्ति

*१७८९. **सेठ गोविन्द दास :** क्या पुनर्वास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस संपत्ति का कुल मूल्य क्या है, जिसका नियंत्रण सरकार ने निष्क्रमणार्थी संपत्ति के नाते अपने हाथ में लिखा था, और जो बाद में उनके मालिकों को लौटा दी गयी ?

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): Information regarding the total value of property, which, although treated at one time as evacuee property, was subsequently restored to